

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न सं0 216  
02 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

विशाखापत्तनम मेट्रो परियोजना

216. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महत्वाकांक्षी विशाखापत्तनम मेट्रो परियोजना (वीएमपी) को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है जिसे 15,933 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है, तथा जिसके वर्ष 2028 की निर्धारित समय-सीमा में कुल 75.3 किलोमीटर की दूरी सहित निर्माण का प्रस्ताव है, जो कोरियाई एक्जिम बैंक द्वारा धनराशि देने में अपनी असमर्थता प्रदर्शित करने के कारण बाधित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शहरी परिवहन प्रणाली को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

(उत्तर)

(आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री)

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): शहरी परिवहन, जो शहरी विकास का अभिन्न अंग है, राज्य का विषय है। इसलिए, व्यापक गतिशीलता योजना, वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने सहित उपयुक्त वित्तपोषण पैटर्न के साथ मेट्रो रेल परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर केंद्र सरकार मेट्रो रेल परियोजनाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर विचार करती है। तथापि, ऐसी परियोजनाओं का अनुमोदन प्रस्ताव की

व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर, 2018 में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में कोरियाई एक्जिम बैंक से बाह्य वित्तीय सहायता हेतु 8,300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विशाखापत्तनम के लिए 42.55 कि.मी. की लंबाई वाली लाइट मेट्रो रेल परियोजना हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथापि, कोरियाई पक्ष ने प्रस्ताव की जांच के पश्चात् परियोजना को वित्तपोषित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। केंद्र सरकार को अब तक आंध्र प्रदेश सरकार से 15,993 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 75.3 कि.मी. लंबी विशाखापत्तनम मेट्रो परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): केंद्र सरकार ने शहरी परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यापक गतिशीलता योजनाएं तैयार करने सहित परिवहन संबंधी विभिन्न अध्ययन करने के लिए निधियां जारी की हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत है:

क्र. सं०.	अध्ययन/रिपोर्ट का नाम	केंद्र सरकार द्वारा जारी निधि (रु. में)	पूर्णता वर्ष
1	विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करना	40,00,000/-	2018-19
2	आंध्र प्रदेश के 9 शहरों अर्थात् एलुरु, काकीनाड, नेल्लोर, आंगोल, राजामुंदरी, अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा और कुरनूल के लिए व्यापक मोबिलिटी प्लान तैयार करना	2,36,00,000/-	2019-2020
3	विजयवाड़ा मेट्रो रेल प्रणाली हेतु दो परिवहन अध्ययनों अर्थात् एकीकृत सार्वजनिक परिवहन योजना (आईपीटी) और गैर-मोटरीकृत परिवहन एकीकरण योजना (एनएमटी) के लिए डीपीआर तैयार करना	78,44,000/-	2018-19

\*\*\*\*\*